उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

मनबोधन लाल श्रीवास्तव

(एस.आर. दास, सी.जे., वेंकटरामा अय्यर, बी.पी. सिन्हा,

जे.एल. कपूर और ए.के. सरकार, जेजे.)

सरकारी कर्मचारी-अनुशासनात्मक कार्यवाही-संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के तहत पूछताछ कारण-सूचना-लोक सेवा आयोग से परामर्श-क्या अनिवार्य है-भारत का संविधान, कला 311(2), 320(3)(सी)।

प्रत्यर्थी अपीलार्थी, उत्तर प्रदेश राज्य के तहत एक कर्मचारी था, और जैसा कि यह पता चला कि उसने अपने निजी हितों को अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के साथ टकराव में आने दिया था, एक विभागीय जांच आयोजित की गई जिसमें उसके खिलाफ आरोप बनाए गए थे। उन्हें अपने बचाव का लिखित बयान प्रस्तुत करने के लिए कहा गया और इसके समर्थन में सबूत पेश करने का अवसर दिया गया। जाँच की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, जिसमें आरोप सही पाए गए थे, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी से भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के तहत, कारण दिखाने के लिए कहा कि उसे क्यों पदावनत नहीं किया जाना चाहिए और अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं किया जाना चाहिए, और प्रत्यर्थी ने अपना बचाव करते हुए और जाँच में अपनाई गई प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए एक लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। इसके बाद, प्रत्यर्थी को रिपोर्ट की एक प्रति दी गई और फिर से कारण दिखाने के लिए कहा गया कि उस पर रैंक में कमी का प्रस्तावित जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए, और उसने एक बार फिर एक लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। इस बीच राज्य लोक सेवा आयोग से सरकार

द्वारा प्रस्तावित सजा के बारे में परामर्श किया गया और इस उद्देश्य के लिए उसे दूसरे कारण बताए जाने के नोटिस की तारीख तक सभी प्रासंगिक सामग्री प्रदान की गई। सरकार ने अंततः 12 सितंबर, 1953 के एक आदेश द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, 2 अगस्त, 1952 से प्रतिवादी के पद को कम कर दिया और इसके बाद, प्रतिवादी ने सरकारी आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कीं। उच्च न्यायालय ने पाया कि हालांकि सरकार द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किया गया था, लेकिन दूसरे कारण दर्शाओ नोटिस के जवाब में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया था, और यह अभिनिर्धारित किया कि सरकार का आदेश इस कारण से अमान्य था कि संविधान के अनुच्छेद 320 (3) (सी) के प्रावधान का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया था। उच्चतम न्यायालय में अपील करने पर अपीलार्थी की ओर से अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की मांग की गई थी ताकि यह दिखाया जा सके कि वास्तव में दूसरे कारण बताएँ नोटिस के जवाब में प्रतिवादी का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के बाद भी राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किया गया था, लेकिन यह पाया गया कि अपीलार्थी के लिए सभी प्रासंगिक सामग्रियों को स्वयं उच्च न्यायालय के समक्ष रखने का पर्याप्त अवसर थाः

(1) यह अभिनिर्धारित किया गया कि अतिरिक्त साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि प्रतिवादी द्वारा दूसरे कारण दर्शाओ नोटिस के जवाब में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के बाद आयोग के साथ कोई परामर्श नहीं किया गया था, कायम रहना चाहिए। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अपीलीय स्तर पर अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ताकि किसी एक पक्ष को उचित स्तर पर अपने मामले को प्रस्तुत करने में खामियों को दूर करने और अंतराल को भरने में सक्षम बनाया जा सके। बेशक, स्थिति अलग है जहां

अपीलीय अदालत को स्वयं पक्षों के बीच न्याय करने में सक्षम बनाने के लिए कुछ सबूत पेश करने की आवश्यकता होती है।

(2) कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 (3) (सी) के प्रावधान अनिवार्य नहीं हैं और वे किसी लोक सेवक को कोई अधिकार प्रदान नहीं करते हैं ताकि परामर्श का अभाव या परामर्श में कोई अनियमितता उसे अदालत में कार्रवाई का कारण न दे।

पी. जोसेफ जॉन बनाम त्रावणकोर-कोचीन राज्य, (1955) आई. एस. सी. आर. 1011 पर विचार किया गया।

विश्वनाथ खामका बनाम राजा सम्राट, (1945) एफ. सी. आर. 99, पर भरोसा किया। (3) कि संविधान का Art.311 अनुच्छेद 320 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित नहीं है।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1955 की संख्या 27 और 28।

सिविल विविध मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 8 जनवरी, 1954 के निर्णय और आदेश के खिलाफ अपील 1953 का लेखन सं. 817।

जी.सी. माथुर और सी.पी. लाल, सी.ए. संख्या 27 में अपीलार्थी और सी.ए. संख्या 28 में प्रत्यर्थी के लिए।

एन.सी. सेन, सी.ए. नं. 27 में प्रत्यर्थी और सी.ए. नं. 28 में अपीलार्थी के लिए।

20 सितंबर 1957

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय सिन्हा जे. द्वारा दिया गया था।

संविधान के अनुच्छेद 132 (1) के तहत उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों पर दो प्रति-अपीलें इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के एक

सामान्य निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती हैं, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दो रिट याचिकाएं संख्या 1953 की संख्या 121 और 817 को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी और आंशिक रूप से खारिज कर दिया गया था, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित आदेशों की वैधता पर सवाल उठाया था, जिससे उसे रैंक में कम किया गया था और सेवा से उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दिया गया था। दीवानी अपील सं. 27 को उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा और दीवानी अपील सं. 28 को याचिकाकर्ता द्वारा नीचे दिए गए न्यायालय में प्राथमिकता दी गई है। संक्षिप्तता के लिए, हम उत्तर प्रदेश राज्य को अपीलार्थी और उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता-श्री मनबोधन लाल के रूप में संदर्भित करेंगे। श्रीवास्तव-प्रतिवादी के रूप में, इस निर्णय के दौरान जिसमें दोनों अपीलें शामिल हैं।

निम्नलिखित तथ्यों को बताना आवश्यक हैः 1920 में, प्रतिवादी उत्तर प्रदेश राज्य के शिक्षा विभाग में कार्यरत था, और नियत समय में, उसे संयुक्त प्रांत शिक्षा सेवा (जूनियर स्केल) में पदोन्नत किया गया था। यह 1946 में हुआ था। वर्ष 1948 में, प्रत्यर्थी को शिक्षा विभाग द्वारा "शिक्षा" शैली के तहत जारी एक त्रैमासिक पत्रिका का विशेष कार्य अधिकारी और प्रबंध संपादक नियुक्त किया गया था। विशेष कर्तव्य पर अधिकारी के पद पर रहते हुए, प्रतिवादी को पुस्तक चयन समिति का सदस्य भी नियुक्त किया गया था। 1951 तक वो वहा रहा, उस समिति के सदस्य के रूप में प्रत्यर्थी का आचरण संतोषजनक और बोर्ड से ऊपर नहीं पाया गया, क्योंकि यह पता चला कि उसने अपने निजी हित को अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के साथ टकराव में आने दिया था। यह पाया गया कि उन्होंने अनुमोदित सूची में पुस्तकों के चयन में, कुछ पुस्तकों के संबंध में, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे उनके भतीजे द्वारा लिखी गई थीं, जिनकी उम्र केवल 14 वर्ष थी, और उनके एक अन्य रिश्तेदार और प्रकाशकों की एक फर्म ने भी, जिन्होंने ब्याज पर उन्हें कुछ राशि अग्रिम दी थी। जुलाई, 1952 में,

प्रत्यर्थी को एक निश्चित हाई स्कूल के हेडमास्टर के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन वह अपने पद पर शामिल नहीं हुए और चिकित्सा आधार पर छुट्टी पर चले गए। छुट्टी पर रहते हुए, प्रतिवादी को 2 अगस्त, 1952 से सेवा से निलंबित कर दिया गया था। सितंबर में, उसी वर्ष, शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी किए, प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोप तैयार किए और उसे बचाव का अपना लिखित बयान प्रस्तुत करने के लिए कहा और उसे इसके समर्थन में सबूत बुलाने का अवसर दिया। इस मामले के प्रयोजनों के लिए, उनके खिलाफ बनाए गए आरोपों को निर्धारित करना आवश्यक नहीं है, सिवाय इसके कि यह कहा जाए कि उनके भतीजे और उनके अन्य संबंधियों द्वारा लिखी गई पुस्तकों का विवरण दिया गया था, आरोपों की गंभीरता यह है कि उन्होंने पुस्तकों के कथित लेखकों के साथ अपने संबंधों के बारे में समिति को सूचित नहीं किया था, जिसके चयन की गणना उन संबंधों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए की गई थी। एक अन्य आरोप उनके प्रकाशकों की एक निश्चित फर्म को लाभान्वित करने से संबंधित था, जिनकी पुस्तकें, लगभग एक दर्जन संख्या में, उस समिति द्वारा चुनी गई थीं, जिसके वे सदस्य थे। प्रत्यर्थी ने अपने बचाव में एक लंबा लिखित बयान प्रस्तुत किया और गवाहों की मौखिक जांच पर जोर नहीं दिया, बल्कि अपने स्पष्टीकरण के साथ अपने मामले के समर्थन में कुछ हलफनामे संलग्न किए। शिक्षा निदेशक ने प्रत्यर्थी के खिलाफ बनाए गए आरोपों की गहन जांच के बाद इस आशय की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि उसके खिलाफ बनाए गए आरोप काफी हद तक साबित हो गए हैं। उन्होंने सिफारिश की कि प्रतिवादी को अधीनस्थ शिक्षा सेवा में पदावनत किया जाए और अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाए।

उपरोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, सरकार ने 7 नवंबर, 1952 को संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के तहत प्रतिवादी को यह कारण दिखाने के लिए बुलाने का फैसला किया कि विभागीय जांच रिपोर्ट में सुझाए गए दंड को उस पर क्यों नहीं लगाया

जाना चाहिए। 13 नवंबर, 1952 को प्रत्यर्थी को दिए गए कारण-प्रकट करने के नोटिस के अनुसरण में, उन्होंने 26 नवंबर, 1952 को एक लंबा लिखित स्पष्टीकरण दिया, उसी तर्ज पर जो उनके लिखित बयान-बचाव के रूप में पहले प्रस्तुत किया गया था, निष्कर्षों के गुण-दोष के साथ-साथ जांच में अपनाई गई प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताते हुए। उन्होंने प्रस्तावित सजा के खिलाफ भी कारण दिखाया। 9 जनवरी, 1953 की एक सरकारी अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जिसमें शिक्षा विभाग के उन अधिकारियों के नाम दिखाए गए थे, जो 55 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति पर नियत समय में सेवानिवृत्त होंगे। प्रत्यर्थी को उनमें से एक के रूप में दिखाया गया है, और सेवानिवृत्ति की तारीखों को दिखाने के लिए अंतिम कॉलम में, 15 सितंबर, 1953 का उल्लेख उनके नाम के सामने किया गया है। 2 फरवरी, 1953 को प्रत्यर्थी ने पहली याचिका (1953 की रिट याचिका संख्या 121) दायर की, जिसमें उन्हें निलंबित करने के सरकार के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई और उनसे कारण बताने का आह्वान किया गया कि उन्हें निलंबन की तारीख से रैंक में क्यों नहीं घटाया जाना चाहिए, और अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त भी होना चाहिए। उस याचिका में, उन्होंने पूरी कार्यवाही की वैधता को भी चुनौती दी और सरकार को निलंबन की अवधि के दौरान उनका पूरा वेतन देने का निर्देश देने के लिए एक अनिवार्य रिट के लिए प्रार्थना की, जब तक कि वे सेवानिवृत्त होने की आयु प्राप्त नहीं कर लेते। शायद, यह महसूस करते हुए कि नवंबर, 1952 में प्रत्यर्थी को दी गई कारण-सूचना संविधान द्वारा विचार किए गए उचित अवसर की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा नहीं करेगी, शिक्षा निदेशक ने प्रत्यर्थी को 16 जून, 1953 को जांच की रिपोर्ट की एक प्रति के साथ भेजा। और फिर से उनसे कारण दिखाने का आह्वान किया कि उन पर पद में कमी का प्रस्तावित जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाए। जांच के परिणामस्वरूप प्रस्तावित दंड के बारे में सरकार द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग (जिसे हम आयोग के रूप में संदर्भित करेंगे) से भी परामर्श किया गया

था। संभवतः, आयोग को दूसरे कारण दर्शाओ नोटिस की तारीख तक सभी प्रासंगिक सामग्री प्रदान की गई थी। आयोग से परामर्श किया गया था लेकिन उच्च न्यायालय के निष्कर्षों से ऐसा प्रतीत होता है कि 3 जुलाई, 1953 को प्रस्तुत प्रतिवादी का लिखित स्पष्टीकरण आयोग के समक्ष नहीं था। 3 जुलाई, 1953 को प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण बहुत अधिक विस्तृत था, जो न केवल उनके खिलाफ लगाए गए तीन आरोपों से संबंधित था, बल्कि जांच अधिकारी के अन्य अप्रासंगिक निष्कर्षों से भी संबंधित था, जिन्होंने प्रतिवादी की दक्षता और आचरण के खिलाफ कई टिप्पणियां की थीं, जो प्रतिवादी के खिलाफ बनाए गए कई आरोपों के प्रमुखों का विषय नहीं थे, और इसलिए, इसकी मांग नहीं की गई थी। आयोग की राय, जांच रिपोर्ट और प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कई स्पष्टीकरणों पर विचार करने के बाद, राज्य सरकार ने 12 सितंबर, 1953 को अपना अंतिम आदेश पारित किया, जिसमें प्रत्यर्थी को 2 अगस्त, 1952 से यू. पी. शिक्षा सेवा (जूनियर स्केल) से घटाकर अधीनस्थ शिक्षा सेवा कर दिया गया और उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया। अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश कमोबेश अनावश्यक था क्योंकि प्रतिवादी 15 सितंबर, 1953 से सामान्य पाठ्यक्रम में सेवानिवृत्त हुआ होगा, जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया था। पहली रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, और उच्च न्यायालय द्वारा आंशिक रूप से इसकी सुनवाई के बाद, प्रतिवादी ने 23 सितंबर, 1953 को दूसरा रिट आवेदन (1953 की रिट याचिका संख्या 817) दायर किया, जिसमें व्यावहारिक रूप से उन्हीं आधारों को शामिल किया गया और उपरोक्त के समान राहत के लिए प्रार्थना की गई। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने 8 जनवरी, 1954 के अपने निर्णय और आदेश द्वारा दोनों रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि विवादित आदेश इस कारण से अमान्य थे कि संविधान के अनुच्छेद 320 (3) (सी) के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया था क्योंकि 3 जुलाई, 1953 को प्रस्तुत प्रतिवादी का अंतिम

लिखित स्पष्टीकरण आयोग के समक्ष नहीं रखा गया था। इसने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया क्योंकि यह उच्च न्यायालय के फैसले से पहले नियत समय पर हुआ था। अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश के इस भाग से अपील संख्या 27 दायर की है। उच्च न्यायालय ने निलंबन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन के संबंध में प्रत्यर्थी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जिसके दौरान वह सरकार के आदेशों द्वारा उससे वंचित था। निर्णय के इस भाग से, प्रतिवादी ने अपील संख्या 28 को प्राथमिकता दी है। यह स्पष्ट है कि यदि राज्य सरकार की अपील अच्छी तरह से आधारित है और इस न्यायालय द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है, तो प्रतिवादी की अपील बिना किसी आगे के विचार के विफल हो जानी चाहिए।

इन अपीलों में उठाए गए विवाद के गुण-दोष पर विचार करने से पहले, यह बताना आवश्यक है कि अपीलार्थी की ओर से उपस्थित श्री माथुर ने इस न्यायालय के समक्ष, तर्क के समय, मूल अभिलेख और कुछ शपथ-पत्र प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा है ताकि यह दिखाया जा सके कि वास्तव में, राज्य सरकार और आयोग के बीच परामर्श से संबंधित सभी प्रासंगिक तथ्य उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं रखे गए थे और यदि अतिरिक्त साक्ष्य इस स्तर पर लिए गए थे, तो वह इस न्यायालय को संतुष्ट करेंगे कि दूसरे कारण बताएँ नोटिस के जवाब में प्रतिवादी के स्पष्टीकरण को प्रस्तुत करने के बाद भी आयोग से परामर्श किया गया था। हमारे सामने रखे जाने वाले प्रस्तावित अतिरिक्त साक्ष्य को देखे बिना, हमने संकेत दिया कि. हम इस स्तर पर अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुमति नहीं देंगे जब राज्य सरकार के पास सभी प्रासंगिक मामलों को स्वयं उच्च न्यायालय के समक्ष रखने का पर्याप्त अवसर है। हम कोई विशेष कारण नहीं देख सके कि इस न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए। यह सुझाव नहीं दिया गया था कि वह सारा मामला जो इस न्यायालय के समक्ष रखा जाना प्रस्तावित था, उस समय राज्य सरकार के लिए

उपलब्ध नहीं था जब उच्च न्यायालय ने दो अवसरों पर रिट याचिकाओं पर विचार किया था। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अपीलीय स्तर पर अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ताकि एक पक्ष को उचित स्तर पर अपने मामले को प्रस्तुत करने में कुछ खामियों को दूर करने और अंतराल को भरने में सक्षम बनाया जा सके। बेशक, स्थिति अलग है जहां अपीलीय न्यायालय को स्वयं पक्षों के बीच न्याय करने में सक्षम बनाने के लिए कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। इस मामले में, इसलिए, हम इस धारणा पर आगे बढ़े हैं कि हालांकि आयोग से प्रतिवादी के अपराध या अन्यथा के बारे में परामर्श किया गया था और पहले कारण-बताने की सूचना के जवाब में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के बाद उसके खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन दूसरे कारण-दिखाने की सूचना के जवाब में प्रतिवादी द्वारा अपना अधिक विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के बाद आयोग के साथ कोई परामर्श नहीं किया गया था।

इसलिए, अपील सं. 27 (1955) में विवाद का मुख्य प्रश्न है का यह है कि क्या उच्च न्यायालय का यह विचार सही था कि अनुच्छेद 311 संविधान के अनुच्छेद 320 (3) (सी) के प्रावधानों के अधीन था, जो अनिवार्य थे, और इस प्रकार, तत्काल मामले में उन प्रावधानों का पालन न करना 12 सितंबर, 1953 को सरकार द्वारा पारित आदेश के साथ समाप्त होने वाली कार्यवाही के लिए घातक था। उच्च न्यायालय ने इस धारणा के साथ शुरुआत की कि संविधान के उपरोक्त प्रावधान अनिवार्य हैं और उस धारणा पर आगे इस सवाल पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा कि क्या राज्य सरकार द्वारा उन प्रावधानों का पालन न करने से प्रतिवादी को इस मामले में विवादित आदेश की वैधता पर सवाल उठाने का कोई अधिकार प्राप्त हुआ है। इस संबंध में, उच्च न्यायालय ने पाया कि आयोग से जून, 1953 में कुछ समय के लिए परामर्श किया गया था। जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह मान लेना होगा कि आयोग ने दूसरे कारण-बताने के नोटिस

के जवाब में 3 जुलाई को प्रतिवादी द्वारा लिखित रूप में अधिक विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया था। उच्च न्यायालय की आगे यह राय थी कि यह हो सकता है कि यदि वह स्पष्टीकरण आयोग के समक्ष रखा गया होता, तो राज्य सरकार को उसकी सलाह उसी संदर्भ में नहीं होती जिसमें उसने वास्तव में अपनी सलाह दी थी, और जिस पर विचार करने के बाद, अन्य प्रासंगिक मामलों के साथ, राज्य सरकार ने अब विचाराधीन आदेश पारित किया। हम इस मामले के प्रयोजनों के लिए मान लेंगे कि आयोग के साथ परामर्श में अनियमितता थी, हालांकि इसकी पूर्ण अनुपस्थिति नहीं थी। अब सवाल यह हैः क्या इस अनियमितता ने प्रतिवादी को 12 सितंबर, 1953 को राज्य सरकार द्वारा पारित अंतिम आदेश को चुनौती देने के लिए कार्रवाई का कारण दिया? आदेश का वह भाग जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित है, आसानी से पारित किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी मामले में, तीन दिन बाद, 15 सितंबर को, प्रतिवादी नियत समय पर सेवानिवृत्त हो गया। इसलिए, सरकार के अंतिम आदेश का परिचालन भाग, जिसने प्रत्यर्थी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, वह आदेश था जिसमें उसे प्रांतीय से अधीनस्थ श्रेणी में कम किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उस आदेश ने संविधान के अनुच्छेद 311 में निर्धारित शर्तों को पूरा किया है। विवाद के किसी भी स्तर पर यह सुझाव नहीं दिया गया है कि, जहां तक अपीलार्थी का संबंध है, प्रत्यर्थी के पास "उसके संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कारण दिखाने का उचित अवसर नहीं था"; कहने का अर्थ यह है कि अब यह सवाल से परे है कि अपीलार्थी द्वारा की गई कार्यवाही, जिसमें प्रत्यर्थी के खिलाफ विभागीय जांच शामिल है, जो उसके पद में कमी के साथ समाप्त होती है, संविधान के भाग XIV के अध्याय । के अनिवार्य प्रावधान को अनुच्छेद 311 के विशेष संदर्भ के साथ संतुष्ट करती है। यह निष्कर्ष प्रत्यर्थी के मामले को समाप्त कर देगा, जब तक कि यह अभिनिर्धारित नहीं किया जाता है कि अनुच्छेद 320 (3) (सी) के प्रावधान एक अनिवार्य चरित्र के हैं और अनुच्छेद 311 के

लिए एक सवार की प्रकृति में हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रश्न का निर्धारण इस न्यायालय द्वारा उस रूप में नहीं किया गया है जिसमें इसे अब हमारे सामने उठाया गया है। पी. जोसेफ जॉन बनाम त्रावणकोर कोचीन राज्य (1) के मामले में, राज्य लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श का सवाल थोड़ी अलग परिस्थितियों में उठाया गया था। लोक सेवक के आचरण की जांच का परिणाम सरकार के सामने आने के बाद, और सजा अस्थायी रूप से आने के बाद, आयोग से परामर्श किया गया और वह प्रस्तावित कार्रवाई के लिए सहमत हो गया। लेकिन यह परामर्श और समझौता लोक सेवक को उसके खिलाफ की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कारण बताने के लिए कहने से पहले था। उनकी शिकायत थी कि आयोग के पिछले आदेश की समीक्षा के लिए सरकार का रुख करने के बाद आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए था और इस न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आयोग से परामर्श करना सरकार का दायित्व नहीं है क्योंकि वह समीक्षा के माध्यम से सरकार का रुख करना चुन सकते हैं। उस मामले में, इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 320 के कथित अनिवार्य चरित्र पर चर्चा और निर्णय नहीं दिया। इसलिए यह माना जा सकता है कि हमें पहली बार इस विवाद का निर्धारण करना होगा, हालांकि अनुच्छेद 320 (3) (सी) के शब्दों के सख्त निर्माण के अनुसार, समीक्षा के लिए एक आवेदन "स्मारक या याचिकाएं" शब्दों द्वारा कवर किया जाएगा।

अनुच्छेद 320 (3) (सी) इन शर्तों में हैः 320 (3):

"संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग, जैसा भी मामला हो, से परामर्श किया जाएगा-

(a).....

(b).....

(c) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सिविल क्षमता में सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामलों पर, जिसमें ऐसे मामलों से संबंधित स्मारक या याचिकाएं शामिल हैं। अनुच्छेद 320 भाग XIV के अध्याय । "सेवाओं" के अंतर्गत नहीं आता है। यह उस भाग के अध्याय ॥ में आता है जिसका नेतृत्व "लोक सेवा आयोग" करता है। अनुच्छेद 320 और 323 लोक सेवा आयोग के कई कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 321 में ऐसे "अतिरिक्त कार्यों" की परिकल्पना की गई है जो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 320 और 323 "यह कर्तव्य होगा" शब्दों से शुरू होता है और फिर संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के विभिन्न कर्तव्यों और कार्यों को निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ता है, जैसे कि नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करना; संयुक्त भर्ती की योजनाओं को तैयार करने और संचालित करने में सहायता करना; और सिविल सेवाओं में नियुक्ति करने में भर्ती के तरीकों या सिद्धांतों से संबंधित सभी मामलों और एक सिविल सेवक को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामलों पर परामर्श किया जाना।"

संभवतः, अनुच्छेद 320 के कई भागों में "होगा" शब्द के उपयोग के कारण, उच्च न्यायालय को यह मानने के लिए प्रेरित किया गया था कि अनुच्छेद 320 (3) (सी) के प्रावधान अनिवार्य थे, लेकिन हमारी राय में, इसके विपरीत होने के कई ठोस कारण हैं। सबसे पहले, अनुच्छेद 320 के परंतुक में ही यह विचार किया गया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, "उन मामलों को निर्दिष्ट करते हुए विनियम बना सकते हैं जिनमें या तो आम तौर पर, या किसी विशेष वर्ग के मामले में या विशेष परिस्थितियों में, लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।" ऊपर उद्धृत शब्द संविधान निर्माताओं के इरादे का स्पष्ट संकेत देते हैं कि उन्होंने कुछ मामलों या मामलों के वर्गों की परिकल्पना की थी जिनमें आयोग से परामर्श करने की आवश्यकता

नहीं थी। यदि अनुच्छेद 320 के प्रावधान अनिवार्य प्रकृति के होते, तो संविधान ने इसके विपरीत विनियम बनाकर उन प्रावधानों को पूर्ववत करने को कार्यकारी सरकार के प्रमुख के विवेक पर नहीं छोड़ा होता। यदि संविधान निर्माताओं का यह इरादा होता कि आयोग के साथ परामर्श अनिवार्य होना चाहिए, तो परंतुक वहां नहीं होता, या किसी भी तरह से, उन शर्तों में नहीं होता जिनमें वह है। यह कहने के बराबर नहीं है कि आयोग के अस्तित्व को नजरअंदाज करना या ऐसे मामलों को चुनना और चुनना जिसमें उससे परामर्श किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, कार्यकारी सरकार के लिए पूरी तरह से खुला है। एक बार प्रासंगिक विनियम बनाए जाने के बाद, उनका अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए और यह बिना कहे चला जाता है कि लोक सेवक को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामलों पर आयोग के साथ परामर्श का विशेष रूप से प्रावधान किया गया है, ताकि पहले सेवाओं को यह आश्वासन दिया जा सके कि एक पूरी तरह से स्वतंत्र निकाय, जो लोक सेवकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आदेशों के निर्माण से सीधे संबंधित नहीं है, ने एक विशेष लोक सेवक के खिलाफ की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई पर खुले दिमाग से विचार किया है। और, दूसरा, लोक सेवाओं के मनोबल को प्रभावित करने वाले मामलों पर सरकार को निष्पक्ष सलाह और राय देना। इसलिए, कार्यकारी सरकार का यह दायित्व है कि जब वह किसी लोक सेवक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव करती है, तो वह आयोग से परामर्श करे कि क्या प्रस्तावित कार्रवाई उचित थी और स्थिति की आवश्यकताओं से अधिक नहीं थी।

दूसरा, यह स्पष्ट है कि आयोग के साथ परामर्श की आवश्यकताओं का विस्तार उन मामलों पर आयोग की सलाह देने तक नहीं है, जो सरकार के लिए बाध्यकारी है, बेशक, सरकार, जब वह इन जैसे मामलों पर आयोग से परामर्श करती है, तो क्या यह केवल औपचारिकता के रूप में नहीं है, बल्कि व्यक्ति के अपराध या अन्यथा का

आकलन करने में उचित सहायता प्राप्त करने की दृष्टि से है और प्रस्तावित दंड की उपयुक्तता और पर्याप्तता का आकलन करने के लिए है। यदि आयोग की राय सरकार के लिए बाध्यकारी थी, तो यह अधिक बल के साथ तर्क दिया जा सकता था कि परामर्श के लिए नियम का पालन न करना एक लोक सेवक के खिलाफ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश की वैधता के लिए घातक होता। इस तरह के बाध्यकारी चरित्र के अभाव में यह देखना मुश्किल है कि अनुच्छेद 320 (3) (सी) के प्रावधानों का पालन न करने से सरकार द्वारा पारित अंतिम आदेश को रद्द करने का प्रभाव कैसे पड़ सकता है।

तीसरा, अनुच्छेद 320 या संविधान के भाग XIV के अध्याय II के अन्य अनुच्छेद आयोग के गठन और आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन और उनकी सेवा की शर्तों के साथ-साथ उनके कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित हैं। अध्याय 2 सरकार और आयोग के बीच संबंध से संबंधित है, लेकिन आयोग और लोक सेवक के बीच नहीं। अनुच्छेद 320 वाला अध्याय 2, संदर्भ में, किसी व्यक्तिगत लोक सेवक को कोई अधिकार या विशेषाधिकार प्रदान नहीं करता है और न ही भाग के अध्याय I, विशेष रूप से अनुच्छेद 311 में निहित प्रकृति की कोई संवैधानिक गारंटी देता है। इसलिए अनुच्छेद 311 किसी भी तरह से भाग 14 के अध्याय 2 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित नहीं है, विशेष रूप से अनुच्छेद 320 के संदर्भ में।

इस प्रश्न को दूसरे दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। क्या संविधान में आकस्मिकता का प्रावधान है कि अनुच्छेद 320 (3) (सी) की आवश्यकताओं का पालन न करने की स्थिति में क्या होगा? यह, या तो स्पष्ट शब्दों में या निहितार्थ से, यह प्रावधान नहीं करता है कि इस तरह के गैर-अनुपालन का परिणाम सरकार के अंतिम आदेश के साथ समाप्त होने वाली कार्यवाही को अमान्य करना है। संविधान के भाग XIV के प्रासंगिक प्रावधानों के इस पहलू का इस सवाल पर सीधा असर पड़ता है कि क्या

अनुच्छेद 320 अनिवार्य है। यह सवाल कि क्या किसी सार्वजनिक निकाय या प्राधिकरण पर शुल्क लगाने वाले कानून में एक निश्चित प्रावधान अनिवार्य था या केवल निर्देशिका थी, मॉन्ट्रियल स्ट्रीट रेलवे कंपनी बनाम नॉरमैंडिन (') के मामले में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति के उनके लॉर्डशिप के सामने उठा। उस मामले में यह सवाल उठाया गया था कि क्या क़ानून द्वारा निर्देशित जूरी सूचियों को संशोधित करने में चूक का प्रभाव जूरी द्वारा दिए गए फैसले को रद्द करने का था। उनके लॉर्डशिप ने माना कि जूरी सूचियों के उचित संशोधन में अनियमितताएं वास्तव में जूरी के फैसले से नहीं बचेंगी। बोर्ड ने अपने निर्णय के दौरान निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

> "यह सवाल कि क्या किसी क़ानून में प्रावधान प्रत्यक्ष रूप से हैं या अनिवार्य हैं, इस देश में बहुत बार उठा है, लेकिन यह कहा गया है कि कोई सामान्य नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है, और हर मामले में क़ानून के उद्देश्य को देखा जाना चाहिए। इस विषय पर मामले मैक्सवेल ऑन स्टैट्यूट्स, 5 वें संस्करण, पी. में एकत्र किए गए पाए जाएंगे। 596 और निम्नलिखित पृष्ठ। जब किसी कानून के प्रावधान किसी सार्वजनिक कर्तव्य के निष्पादन से संबंधित होते हैं और मामला ऐसा होता है कि इस कर्तव्य की उपेक्षा में किए गए कृत्यों को अमान्य ठहराना गंभीर-सामान्य असुविधा या उन व्यक्तियों के लिए अन्याय होगा, जिन्हें कर्तव्य सौंपे गए लोगों पर कोई नियंत्रण नहीं है, और साथ ही साथ विधानमंडल के मुख्य उद्देश्य को बढ़ावा नहीं देता है, तो ऐसे प्रावधानों को केवल निर्देशिका के रूप में रखने की प्रथा रही है, उनकी उपेक्षा, हालांकि दंडनीय है, जो किए गए कार्यों की वैधता को प्रभावित नहीं करती है।"

इस मामले में निर्धारित सिद्धांत को संघीय न्यायालय द्वारा विश्वनाथ खेमका बनाम राजा सम्राट (2) के मामले में अपनाया गया था। उस मामले में, संघीय न्यायालय को एस के प्रावधानों के गैर-अनुपालन पर प्रभाव पर विचार करना था। भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 256, जिसमें मजिस्ट्रेट शक्तियों या बढ़ी हुई मजिस्ट्रेट शक्तियों आदि को प्रदान करने से पहले सार्वजनिक प्राधिकरणों के बीच परामर्श की आवश्यकता होती है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि धारा 256 के प्रावधान, उपरोक्त, अनिवार्य थे। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि उस धारा का पालन न करने से नियुक्ति अन्यथा नियमित रूप से और वैध रूप से, अमान्य या निष्क्रिय नहीं होगी। यह निर्णय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि संघीय न्यायालय के उनके अधिपत्य के समक्ष तब धारा के शब्द बहुत जोरदार और निषेधात्मक थे।

अनुच्छेद 320 की शर्तों की जांच से पता चलता है कि "होगा" शब्द उस अनुच्छेद के लगभग हर पैराग्राफ और हर खंड या उपखंड में दिखाई देता है। यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अनुच्छेद 320 (3) (ग) के प्रावधान संदर्भ में अनिवार्य हैं, तो अन्य खंडों या उपखंडों या उस अनुच्छेद को समान रूप से अनिवार्य अभिनिर्धारित करना होगा। यदि वे इस प्रकार आयोजित किए जाते हैं, तो संघ या किसी राज्य की लोक सेवाओं के लिए कोई भी नियुक्ति, खंड में इन उपखंडों की शर्तों का सख्ती से पालन किए बिना की जाती है। अनुच्छेद 320 का (3), लोक सेवा में इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, उसकी ओर से कोई गलती नहीं होगी और मामले में उसका कोई कहना नहीं होगा। संविधान निर्माताओं द्वारा इस परिणाम पर विचार नहीं किया जा सकता था। इसलिए, किसी कानून में "होगा" शब्द का उपयोग, हालांकि आम तौर पर एक अनिवार्य अर्थ में लिया जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि हर मामले में इसका प्रभाव होगा, जिसका अर्थ है कि जब तक कानून के शब्दों का समय पर पालन नहीं किया जाता है, तब तक कार्यवाही या कार्यवाही का

परिणाम अमान्य होगा। दूसरी ओर, यह कहना हमेशा सही नहीं है कि जहां "हो सकता है" शब्द का उपयोग किया गया है, कानून केवल अनुमेय या सीधे इस अर्थ में है कि उन प्रावधानों का पालन न करने से कार्यवाही अमान्य नहीं हो जाएगी। उस संबंध में, 'सांविधिक निर्माण'-कला पर क्रॉफर्ड का निम्नलिखित उद्धरण पी पर 261 (516) प्रासंगिक हैः

> "यह सवाल कि क्या कोई क़ानून अनिवार्य है या निर्देशिका विधायिका के इरादे पर निर्भर करती है न कि उस भाषा पर जिसमें इरादे को पहना जाता है। विधायिका के अर्थ और इरादे को नियंत्रित करना चाहिए, और इन्हें न केवल प्रावधान के वाक्यांश से, बल्कि इसकी प्रकृति, इसकी रूपरेखा और इसके किसी न किसी रूप में अर्थ लगाने से होने वाले परिणामों पर विचार करके भी निर्धारित किया जाना चाहिए।"

हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि संविधान का अनुच्छेद 320 (3) (सी) किसी लोक सेवक को कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है ताकि परामर्श का अभाव या परामर्श में कोई अनियमितता, उसे अदालत में कार्रवाई का कारण न दे, या उसे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की विशेष शक्तियों के तहत या अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय की विशेष शक्तियों के तहत राहत का हकदार न बनाए। यह ऐसा अधिकार नहीं है जिसे किसी रिट द्वारा मान्यता दी जा सके और लागू किया जा सके। दूसरी ओर, संविधान के अनुच्छेद 311 का अर्थ संघ या राज्य के सिविल सेवक को अधिकार प्रदान करने के रूप में किया गया है, जिसे वह अदालत में लागू कर सकता है। इसलिए, यदि इस मामले में अनुच्छेद 311 के प्रावधानों का पालन किया गया है और किसी भी स्तर पर यह तर्क नहीं दिया गया है कि उनका पालन नहीं किया गया

है, तो राज्य सरकार द्वारा की गई किसी भी अनियमितता के खिलाफ उनके पास कोई उपाय नहीं है। जब तक यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है, और हम यह अभिनिर्धारित करने के लिए तैयार नहीं हैं कि अनुच्छेद 320 (3) (सी) अनुच्छेद 311 के प्रवर्तक या परंतुक की प्रकृति का है, तब तक अनुच्छेद 320 (3) (सी) का अर्थ उस लोक सेवक को कार्रवाई का कारण देने के अर्थ में नहीं लगाया जा सकता है जिसके खिलाफ उसके नियोक्ता द्वारा कुछ कार्रवाई की गई है।

इन विचारों को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 320 (3) (सी) के प्रावधान अनिवार्य नहीं हैं और उन प्रावधानों का पालन न करने से प्रतिवादी के खिलाफ अदालत में कार्रवाई का कारण नहीं बनता है। यह इस न्यायालय के लिए आगे विचार करने के लिए नहीं है कि प्रतिवादी के पास क्या अन्य उपाय है, यदि कोई हो। इसलिए, अपील No.27 की अनुमति दी जाती है और अपील संख्या 28 खारिज कर दी जाती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी ने संविधान के अनुच्छेद 320 (3) (सी) की शर्तों का सख्ती से पालन नहीं किया, हम निर्देश देते हैं कि प्रत्येक पक्ष पूरे समय अपनी लागत वहन करे।

अपील सं. 21 को अनुमति दी गई।

अपील संख्या 28 खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सपना राजपुरोहित द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।